

- 1 C  
Ex. इस समस्या के तीन महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में कोविड-19 लॉकडाउन, विमुद्रीकरण और तनावग्रस्त बैंकिंग क्षेत्र, जीएसटी कार्यान्वयन और कृषि क्षेत्र में समस्याएं शामिल हैं। सार्वजनिक सामान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और सरकार को उनकी आपूर्ति के लिए कर राजस्व की आवश्यकता होती है, और ये राष्ट्रीय आय पर निर्भर करते हैं। फिर रोजगार है। श्रम की मांग तभी होती है जब माल की मांग होती है। इसलिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विकास आवश्यक है।
- 2 A  
Ex. प्रचलन बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। यही कारण है कि यहां श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है।
- 3 A  
Ex. प्रचलन में मुद्रा में प्रचलन में नोट, रुपये के सिक्के और जनता के पास और बैंकों के पास छोटे सिक्के शामिल हैं।
- 4 C  
Ex. यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए है और इसमें स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, मध्याह्न भोजन श्रमिक, निर्माण श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। देश में अनुमानित 42 करोड़ ऐसे असंगठित कामगार हैं। इस योजना के तहत, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्राप्त होगी और पेंशन का 50% लाभार्थी की मृत्यु के बाद लाभार्थी के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
- 5 A  
Ex. कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद = शुद्ध मूल्य वर्धन + मूल्यह्रास सही है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद देश के भीतर सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्यवर्धन का योग है।
- 6 C  
Ex. CPI में भोजन का भार 50% तक और WPI में 39.06% है। WPI मुद्रास्फीति मूल्य परिवर्तन पर कब्जा नहीं करती है लेकिन CPI करता है।
- 7 C  
Ex. सीपीआई उपभोक्ता द्वारा दुकानदारों को भुगतान की गई औसत कीमत की गणना करता है। सीपीआई शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, परिधान, खाद्य और पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा देखभाल जैसे खर्चों को मापता है।
- 8 C  
Ex. मुख्य मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कम अस्थिर है। आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई हेडलाइन को ट्रैक करता है।
- 9 D  
Ex. भारत में केवल NBFC-MFI ही माइक्रोफाइनेंस ऋण देते हैं। एनबीएफसी-एमएफआई माइक्रोफाइनेंस ऋण संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं हैं। एनबीएफसी-एमएफआई बाजार सिद्धांत के आधार पर माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर ब्याज दर वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।
- 10 C  
Ex. सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित, बीड जिला किसी भी बीमा कंपनी के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। 2020 के खरीफ सीजन के दौरान, कार्यान्वयन के लिए निविदाओं पर कोई बोली नहीं लगी। इसलिए, राज्य के कृषि विभाग ने जिले के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव करने का फैसला किया। राज्य द्वारा संचालित भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने इस योजना को लागू किया। नए दिशानिर्देशों के तहत, बीमा कंपनी ने एकत्र किए गए प्रीमियम के 110 प्रतिशत का कवर प्रदान किया, जिसमें चेतावनी दी गई थी। यदि मुआवजा प्रदान किए गए कवर से अधिक हो गया, राज्य सरकार पुल राशि का भुगतान करेगी। यदि मुआवजा एकत्र किए गए प्रीमियम से कम था, तो बीमा कंपनी राशि का 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में रखेगी और बाकी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करेगी।
- 11 A  
Ex. वित्त वर्ष 2011 की जून तिमाही के जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोनावायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है। जबकि महामारी की चपेट में आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से धीमी हो रही थी, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के 40 वर्षों में पहली बार वित्त वर्ष 2011 में मंदी की चपेट में आने की उम्मीद है।
- 12 D  
Ex. स्टैगफ्लेशन दो आर्थिक शब्दों "ठहराव" और "मुद्रास्फीति" का एक संयोजन है। इसका तात्पर्य है, आर्थिक परिदृश्य जो एक अर्थव्यवस्था के भीतर कम जीडीपी विकास दर, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर के एक साथ अस्तित्व को दर्शाता है।
- 13 D  
Ex. जी-एसआईबी के लिए बेसल समिति की मूल्यांकन पद्धति के लिए बैंकों के एक नमूने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को संकेतकों के एक सेट की रिपोर्ट करें। इन संकेतकों को तब एकत्र किया जाता है और नमूने में बैंकों के स्कोर की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। कट-ऑफ स्कोर से ऊपर के बैंकों को जी-एसआईबी के रूप में पहचाना जाता है और उन्हें बकेट के लिए आवंटित किया जाता है जिसका उपयोग उनकी उच्च हानि अवशोषण आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 14 B  
Ex. गोल्डन शेरर वह हिस्सा है जो अन्य शेररधारकों के निर्णयों को वीटो करने के लिए स्वर्ण शेरर रखने वाली इकाई को सक्षम बनाता है। गोल्डन शेररधारक निर्णय को वीटो कर सकता है, भले ही उसके पास बहुसंख्यक शेरर न हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के मामले में, सरकार वीटो पावर का प्रयोग कर सकती है (यदि उसके पास गोल्डन शेरर है) तब भी जब उसके पास 51% से कम स्वामित्व हो।













